

लोक प्रशासन / PUBLIC ADMINISTRATION

प्रश्न-पत्र II / Paper II

निर्धारित समय : तीन घंटे

Time Allowed : Three Hours

अधिकतम अंक : 250

Maximum Marks : 250

प्रश्न-पत्र के लिए विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें :

इसमें आठ प्रश्न हैं जो दो खण्डों में विभाजित हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं ।

परीक्षार्थी को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर देने हैं ।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं तथा बाकी में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं ।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए । उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे ।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए ।

प्रश्नों के उत्तरों की गणना क्रमानुसार की जाएगी । यदि काटा नहीं हो, तो प्रश्न के उत्तर की गणना की जाएगी चाहे वह उत्तर अंशतः दिया गया हो । प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए ।

Question Paper Specific Instructions

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

There are **EIGHT** questions divided in **TWO SECTIONS** and printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.

Candidate has to attempt **FIVE** questions in all.

Questions no. **1** and **5** are compulsory and out of the remaining, any **THREE** are to be attempted choosing at least **ONE** from each section.

The number of marks carried by a question / part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Attempts of questions shall be counted in sequential order. Unless struck off, attempt of a question shall be counted even if attempted partly. Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

खण्ड A

SECTION A

Q1. निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Attempt all of the following questions in about 150 words each : 10×5=50

- (a) “1773 के विनियमन (रेग्यूलेटिंग) अधिनियम द्वारा न केवल प्रशासन में मान्यताओं को सन्निविष्ट किया गया अपितु इसके द्वारा भारत में केन्द्रीकृत प्रशासन की नींव भी पड़ी।” व्याख्या कीजिए।

“The Regulating Act of 1773 not only introduced values in administration but also laid the foundation of centralized administration in India.” Explain.

10

- (b) क्या आपके विचार में संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित कतिपय आदर्श आज भी केवल कागज पर रह गए हैं ? आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

Do you think that some of the ideals enshrined in the Preamble of the Constitution remain only on paper even today ? Critically evaluate.

10

- (c) भारत में सहकारी संघवाद को पुनःपरिभाषित तथा क्रियान्वित करने के लिए उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता का परीक्षण कीजिए।

Examine the efficacy of the measures taken to redefine and execute cooperative federalism in India.

10

- (d) उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के सन्दर्भ में महारत्ना, नवरत्ना और मिनीरत्ना किस्म के सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की क्षमता तथा उनकी निष्पादनशीलता का मूल्यांकन कीजिए।

Evaluate the performance and efficacy of the Maharatna, Navratna and Miniratna type of Public Sector Undertakings in the context of Liberalization, Privatization and Globalization (LPG).

10

- (e) “विकास क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का राज्य की घटती हुई वैधता से सम्बन्ध काफ़ी गहरा है।” व्याख्या कीजिए।

“The growing prominence of NGOs in development areas is strongly related to the declining legitimacy of the State.” Explain.

10

Q2. (a) “वर्तमान समय में कौटिल्य का अर्थशास्त्र आर्थिक मामलों की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में अधिक प्रासंगिक है।” इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

“In contemporary times, Kautilya’s Arthashastra is relevant more in the field of international relations than in economic affairs.” Analyse the statement. 20

(b) “प्रभावी केन्द्रीकृत प्रशासन का, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी निर्णायक और सत्तात्मक नेतृत्व से परस्पर सम्बन्ध है।” स्वतन्त्रता से अब तक के सुसंगत उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए।

“Dominant centralized administration is correlated with decisive and authoritative leadership provided by the Prime Minister’s office.” Explain with suitable examples since independence. 20

(c) “भारत में मुगल शासन की एक महत्वपूर्ण विरासत, राज्य तथा जिला स्तरों पर सुव्यवस्थित भू-राजस्व प्रशासन है।” अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।

“A significant legacy of the Mughal rule in India is a well-organized revenue administration at the State and District levels.” Comment. 10

Q3. (a) गृह मंत्रालय की भूमिका के विस्तार के लिए किन घटकों का योगदान रहा है ? अपने दायित्वों को अधिक प्रभावशाली ढंग से निष्पादित करने के लिए यह रक्षा मंत्रालय के साथ किस प्रकार का समन्वय स्थापित कर सकता है ?

What factors have led to the expansion of the role of the Ministry of Home Affairs ? How can it coordinate its affairs more effectively with the Ministry of Defence ? 20

(b) “वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के निःसंदेह आर्थिक लाभ हैं, किन्तु यह राज्य के कर लागू करने के अन्तर्निहित अधिकार से समझौता करने की ओर प्रवृत्त होगा।” इस संदर्भ में संघ-राज्य वित्तीय सम्बन्धों की बदलती प्रकृति पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।

“Introduction of G.S.T. (Goods and Services Tax) no doubt has economic benefits, but tends to compromise the States’ inherent right to impose taxes.” In this context, comment on the changing nature of Union-State financial relations. 20

(c) “भारत में नियोजन, आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन की चुनौतियों को हल करने में विफल रहा है।” नीति आयोग के निर्गमन के सन्दर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिए।

“Planning in India has failed to meet the challenges of economic development and social change.” Discuss the statement in the context of the emergence of NITI Aayog. 10

- Q4. (a) “उच्चतम न्यायालय तथा संघ (केन्द्र) सरकार के मध्य न्यायपालिका में नियुक्तियों के मामलों पर वैचारिक अनुरूपता की अनुपस्थिति के कारण न्यायिक व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा है।” उपर्युक्त कथन के आलोक में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (ए.आई.जे.एस.) के गठन के प्रस्ताव का परीक्षण कीजिए।

“The absence of congruence of views on appointments to judiciary between the Supreme Court and the Union Government has had an adverse impact on the judicial system.” In the light of the above statement, examine the proposal to constitute an All India Judicial Service (AIJS).

20

- (b) “अनेक राज्यों में नियामकीय और विकासात्मक कार्यों के पृथक्करण ने न केवल जिला कलेक्टर अपितु विकास प्रशासन को भी कमजोर कर दिया है।” इस नीति पर पुनर्विचार की आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

“The separation between regulatory and development functions in many States has not only weakened the District Collector but also development administration.” Critically examine the need to relook at this policy.

20

- (c) “विधान-मंडल सुसंगत नीति निर्माण करने की अपेक्षा आपसी मतभेद स्थल का रूप ले चुके हैं।” राज्य सरकारों के काम-काज के तरीकों के संदर्भ में टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए।

“Legislatures have become a place for infighting rather than for proper policy making.” Comment in the context of the working of State Governments.

10

ABHYAS
IAS ACADEMY
Basics to Brilliance

खण्ड B

SECTION B

Q5. निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए :

Attempt all of the following questions in about 150 words each : 10×5=50

- (a) “उच्च सिविल अधिकारियों को प्राप्त स्वायत्तता उनकी सृजनात्मक अभिव्यक्ति एवं उत्पादिता में वृद्धि करती है।” सिविल सेवा को अधिक जवाबदेह तथा नवप्रवर्तक बनाने के लिए अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए।

“Autonomy granted to higher civil servants tends to increase their creativity and productivity.” Argue the case to make the civil service more accountable as well as innovative. 10

- (b) गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियों (एन.पी.ए.) के परिणामस्वरूप उत्पन्न संकट से उभरने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को बजट सम्बन्धी सहायता दी जाती है। यह नीति कहाँ तक उचित है, इसके संदर्भ में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए।

Justify the budgetary support to nationalized banks to overcome the crisis resulting out of Non-Performing Assets (NPA). 10

- (c) “अनेक आलोचकों के द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को आर्थिक विकास के लिए बाधक माना जाता है।” इस कथन का मूल्यांकन करते हुए अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

“National Green Tribunal is viewed by many critics as a hindrance to economic development.” Evaluate the statement and give arguments in support of your answer. 10

- (d) क्या भारत में पुलिस प्रशिक्षण अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता को प्रतिबिम्बित करती है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए।

Is training of police in India still a reflection of the colonial mindset? Give reasons for your answer. 10

- (e) “‘नव स्थानिकवाद’ के सिद्धान्त का, राज्य सरकारों तथा स्थानीय सरकारी निकायों के बीच रिश्तों की उभरती प्रकृति से सम्बन्ध है।” व्याख्या कीजिए।

“The concept of ‘new localism’ is related to the emerging nature of the relationship between the State Governments and local government bodies.” Explain. 10

- Q6.** (a) “सुशासन के लक्ष्य काल्पनिक रह जाएँगे यदि स्थानीय शासन, जो नागरिकों को सीधे मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाता है, को 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अपेक्षित अनिवार्य अधिकारों से अधिकृत नहीं कर दिया जाता है।” स्थानीय शासन की संस्थाओं के सशक्तिकरण की स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

“The goals of good governance will remain utopian if local governments, responsible for providing all basic services directly to the citizens, are not empowered as mandated by the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts.” Critically evaluate the status of empowerment of the local bodies.

20

- (b) राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन योजना (एन.डी.एम.पी.) आपदा प्रबन्धन चक्र की सभी प्रावस्थाओं के अन्तर्गत सरकारी एजेंसियों के लिए किस प्रकार से दिशा-निर्देश एवं रूपरेखा तैयार करती है ? व्याख्या कीजिए।

Explain how the National Disaster Management Plan (NDMP) provides a framework and direction to the government agencies for all phases of disaster management cycle.

20

- (c) रेल बजट के सामान्य बजट में प्रस्तावित विलयन से आप किन लाभों की प्रत्याशा कर सकते हैं ?

What merits do you foresee in the proposed merger of the Railway Budget with the General Budget ?

10

- Q7.** (a) “सूचना का अधिकार अधिनियम एक ऐसा पथ-अग्रणी विधायन है जो गोपनीयता के अँधेरे से पारदर्शिता के उजाले की ओर जाने का संकेत देता है।” नागरिकों को सरकार से सूचना प्राप्त करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? व्याख्या कीजिए कि सूचना के अधिकार के तहत सरकार द्वारा सूचना देने में अनिच्छा की समस्या से कैसे निपटा जा सकता है।

“The Right to Information Act is a path-breaking legislation which signals the march from darkness of secrecy to dawn of transparency.” What hurdles do the citizens face in obtaining information from the government ? Explain how the reluctance of the government to part with information under R.T.I. can be addressed.

20

- (b) “73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्थानीय निकायों को प्राप्त राजकोषीय अंतरण से सम्बन्धित उद्देश्य राज्य वित्त आयोगों की वास्तविक कार्यप्रणाली के परिणामस्वरूप भटक गए हैं।” टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए।

“The objectives of fiscal devolution to local bodies as mandated by the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts has been derailed by the actual working of the State Finance Commissions.” Comment.

20

- (c) “आयकर विभाग के काला धन प्रकटीकरण की पहल के प्रति मिश्रित अनुक्रिया प्राप्त हुई है।” इस जटिल समस्या से निपटने के लिए सुझाव दीजिए।

“The initiative of the Income Tax Department on disclosure of black money has had a mixed response.” Give suggestions for tackling this complex problem.

10

- Q8. (a) क्या आप सहमत हैं कि सातवें नेतन आयोग की सिफ़ारिशों नेतन बढ़ोतरी के साथ-साथ सिविल सेवा सुधार और जवाबदेही की आवश्यकता को सहसम्बन्धित और प्रतिबिम्बित नहीं करती हैं ? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए।

Do you agree that the Seventh Pay Commission's recommendations do not reflect and correlate the need for civil service reforms and accountability with pay increase ? Justify your answer.

20

- (b) “लोकतांत्रिक राजनीति के सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और सत्यनिष्ठा की किसी अवधारणा की परिधि में न केवल राजनेताओं और सिविल सेवकों को बल्कि नागरिकों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।” विवेचना कीजिए।

“In a democratic polity, any conception of ethics and integrity in public life must encompass not only politicians and civil servants but also citizens.” Discuss.

20

- (c) “भारत में पुलिस सुधार एक विवादग्रस्त विषय रहा है।” आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
“Police reforms in India have remained a contentious issue.” Critically analyse.

10

ABHYAS
IAS ACADEMY
Basics to Brilliance

